सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं, ये आपको बर्बाद कर देगा।

–चाणक्य

मूल्य ₹ 3/-

सांध्य दैनिक 4PM

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_SanjayS YouTube @4pm NEWS NETWORK

● वर्षः 12 ● अंक 131 पृष्ठः 8 ● लखनऊ, बुधवार 17 जून, 2026

सेमीफाइनल की राह आसान करने उतरेगी... 7 | राम मंदिर चढ़ावे में धांधली बनेगा... 3 | जब भगवान एफआईआर दर्ज करेंगे... 2

अब उद्धव के सांसदों पर सियासी डाका?

क्या जनादेश बोली लगाकर खरीदा जाएगा

» पश्चिम बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी टूट की आहट

» राज्यसभा की गणित के लिए फिर बदले जाएंगे जनादेश के मायने?

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? जनता का वोट। जनता का भरोसा। जनता का दिया हुआ जनादेश। लेकिन सवाल यह है कि यदि चुनाव के बाद चुने हुए जनप्रतिनिधि ही किसी दूसरे राजनीतिक खेमे में चले जाएं तो फिर वोट जनता ने दिया था या किसी राजनीतिक मंडी ने? महाराष्ट्र की राजनीति में उठ रहा नया तूफान इसी सवाल को एक बार फिर देश के सामने खड़ा कर रहा है।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ जो हुआ था अब वही पटकथा महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) के लिए लिखी जा रही है? उद्धव ठाकरे के 9 सांसदों में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे खेमे की ओर झुक चुके हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कुछ ही दिनों के भीतर दूसरी बार दिल्ली में सांसदों की आपात बैठक बुलानी पड़ी है। यह केवल एक बैठक नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक विरासत और अस्तित्व को बचाने की कोशिश दिखाई दे रही है।

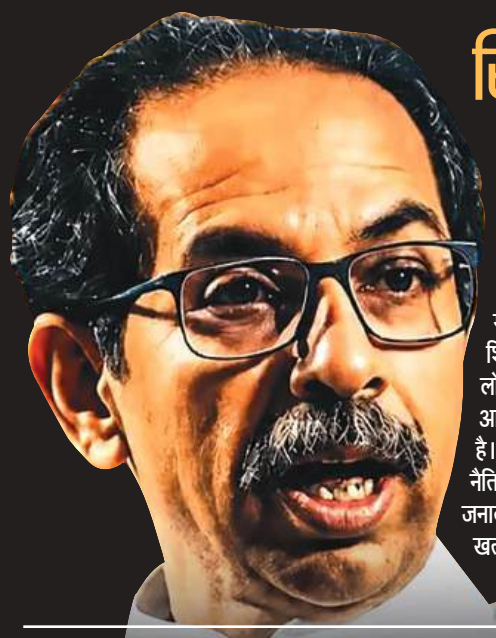

सियासी बवंडर सिर्फ शिवसेना यूबीटी का संकट नहीं

महाराष्ट्र में उठ रहा यह सियासी बवंडर सिर्फ शिवसेना (यूबीटी) का संकट नहीं है। यह भारतीय लोकतंत्र के सामने खड़ा एक बड़ा आईना है। आईना जिसमें सवाल सत्ता का नहीं व्यवस्था का है। सवाल किसी एक दल का नहीं लोकतांत्रिक नैतिकता का है। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या जनादेश अब भी जनता का रहता है या फिर चुनाव खत्म होते ही वह राजनीतिक सौदेबाजी की मेज पर रख दिया जाता है?

बगावत को कुचलने की उद्धव की एक और कोशिश

पार्टी के अंदर चल रही उथल-पुथल के बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने एक बार फिर सांसदों की बैठक बुलाई है। इसके पहले रविवार को सांसदों की बैठक बुलाई गयी थी जिसमें तीन सांसद शामिल हुए थे। शिवसेना (यूबीटी) के लोकसभा मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने सांसदों को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा गया है कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों को सूचना दी जाती है कि पार्टी के विभिन्न मुद्दों को लेकर संसदीय दल की अहम बैठक गुरुवार, 18 जून, 2026 को दिन में 11:00 बजे, संसदीय दल कार्यालय 128-ए, संविधान सदन, संसद भवन, नई दिल्ली में रखी गई है। पार्टी के सभी लोक सभा सदस्यों से निवेदन है कि बैठक में अनिवार्य रूप से मौजूद रहें।

कांग्रेस का शाह पर साजिश रचने का लगाया आरोप

इससे पहले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अलग कर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) में शामिल करने की साजिश रची। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस कदम का मकसद एनडीए की लोकसभा में ताकत बढ़ाना था। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिश भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बड़ा झटका है।

बैठक में नहीं पहुंचे थे सांसद

इससे पहले रविवार को उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई थी। 9 लोकसभा सदस्यों में से अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजभाऊ वाजे और संजय पाटिल व्यक्तिगत रूप से बैठक में शामिल हुए थे। संजय राउत ने बताया था कि ओमप्रकाश राजे निंबालकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश बापुराव पाटिल अष्टिकर और संजय देशमुख ने ऑनलाइन बैठक में भाग लिया, जबकि संजय जाधव ने फोन पर ठाकरे से बात की। बता दें कि शिवसेना यूबीटी के वर्तमान में 9 सांसद हैं और 19 विधायक हैं। वहीं, 16 जून को शिवसेना (उद्धव बाला साहेब ठाकरे) के सांसद अरविंद सावंत ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के निर्देश पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र के जरिए पार्टी के कुछ सांसदों को अलग समूह के रूप में मान्यता दिए जाने अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय की संभावनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई गई है। इसके साथ ही मांग की गई है कि बागी सांसदों को अलग मान्यता न दिया जाए।

पूरा घटनाक्रम राज्यसभा की राजनीतिक से जुड़ा?

वास्तव में यह पूरा घटनाक्रम राज्यसभा की आगामी राजनीति से जुड़ा हुआ है, तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। क्या संसद के ऊपरी सदन की सीटों की गणित के लिए लोकसभा के जनादेश को पुनर्लेखित किया जा रहा है? क्या चुने हुए सांसद अब जनता के प्रतिनिधि कम और राजनीतिक शतरंज के मोहरे ज्यादा बनते जा रहे हैं? उधर उद्धव ठाकरे अपने सांसदों और विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश में जुटे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर संभावित बागियों को अलग मान्यता न देने की मांग की जा चुकी है। बैठकों का दौर जारी है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह नहीं है कि बैठक में क्या होगा, बल्कि यह है कि बैठक के बाद कौन बचेगा और कौन जाएगा। देश के सामने आज कुछ ज्वलंत सवाल खड़े हैं। क्या लोकतंत्र में जनादेश की कोई कीमत बची है? क्या दल बदल विरोधी कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या राजनीतिक दलों को तोड़ना अब चुनाव जीतने से आसान रास्ता बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल यदि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बार-बार इस तरह राजनीतिक पाला बदलते रहेंगे तो आने वाले समय में मतदाता किस पर भरोसा करेगा?

चल रही है पर्दे के पीछे राजनीतिक इंजीनियरिंग

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह महज वैचारिक असहमति है? क्या सांसद अचानक अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हो गए हैं? या फिर पर्दे के पीछे कोई ऐसी राजनीतिक इंजीनियरिंग चल रही है जिसकी गूंज आने वाले राज्यसभा चुनावों तक सुनाई देगी? विपक्ष के नेता खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि सांसदों को पाला बदलने के लिए भारी भरकम ऑफर दिए जा रहे हैं। आरोपों की सच्चाई जांच का विषय हो सकती है लेकिन सवालों की आग बुझ नहीं रही। लोकतंत्र में दल बदल कोई नया शब्द नहीं है लेकिन अब यह एक राजनीतिक संस्कृति बनती जा रही है। जनता एक दल के नाम पर वोट देती है नेता चुनाव जीतता है और फिर किसी दूसरे झंडे के नीचे पहुंच जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा धोखा किसके साथ होता है? पार्टी के साथ या उस मतदाता के साथ जिसने अपनी उम्मीदों का वोट दिया था? यदि जनादेश चुनाव परिणाम आने के बाद ही बदल जाना है तो फिर चुनावों का अर्थ क्या रह जाता है?

विधायकों के साथ अलग से मीटिंग

इसके अलावा शिवसेना (यूबीटी) ने 22 जून को शाम चार बजे पार्टी कार्यालय में सभी विधायकों की मीटिंग बुलाई है। मुख्य सचेतक सुनील प्रभु और एमएलसी अनिल परब की ओर से लिखे पत्र में कहा गया, शिवसेना (यूबीटी) विधायक दल (विधानसभा और विधान परिषद दोनों) के सभी सदस्यों की बैठक 22 जून को शाम 4 बजे मुंबई में मंत्रालय के सामने स्थित शिवालय में बुलाई गई है। पार्टी प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे इस बैठक में मार्गदर्शन करेंगे। आपसे अनुरोध है कि उक्त बैठक में समय पर उपस्थित हों।

महुआ मोइत्रा के इस विषय पर विवादित पोस्ट

महुआ मोइत्रा सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सिर्फ 15 करोड़ रुपए? सस्ते में क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है हमारे को 4 करोड़ रुपए अग्रिम और अगले 36 महीनों के लिए हर महीने 1 करोड़ रुपए मिला है। ... हनी प्लस मनी। महुआ ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि एनसीपीआई तो कुत्ते की पूंछ का आखिरी बाल भी नहीं है। असली कुत्ता तो टीएमसी से अलग हुआ गुट है। अब एनसीपीआई से उम्मीद की जा रही है कि वही उस कुत्ते को नचाए। यह बिल्कुल संभव नहीं है। अभिषेक मनु संघवी का धन्यवाद, जिन्होंने बात को उसी तरह कहा जैसी वह वास्तव में है!

जब भगवान एफआईआर दर्ज करेंगे तो कैसे बचेंगे बीजेपी वाले : अखिलेश यादव

» राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन के मामले पर फिर बरसे सपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा प्रमुख का भाजपा की डबल सरकार पर डबल अटैक जारी है। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की रकम के गबन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर फिर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा, कि उस समय जब चढ़ावे को लेकर चिंता है, उस समय आप दान कर रहे हैं, एक दूसरे से सहयोग लेकर भंडारा कर रहे हैं, पेट पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भगवान एफआईआर दर्ज करेंगे तो कैसे बचेंगे।

अखिलेश ने राम मंदिर गबन मामले में कानूनी कार्रवाई के सवाल पर कहा, हमारी आपकी कानूनी एफआईआर संविधान वाली है वह अलग विषय है लेकिन जो भगवान की एफआईआर लिख जाएगी उसका क्या करोगे आप? उन्होंने आगे कहा कि हमें पता चला है दो बड़े डबल इंजन को पैसा जा रहा था। प्रभु श्री राम को मानने वाले, उनके रास्ते पर चलने वाले बहुत दुखी हैं।

अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव और इंडिया गठबंधन के सवाल पर कहा कि जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। अभी-अभी हराया है बीजेपी को, हारी हुई बीजेपी है, मरता क्या ना करता. उन्होंने आगे कहा कि 027 में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता से ज्यादा जनता तैयार है ये सरकार ने रूमर फैलाया है कि नवंबर में चुनाव करा देंगे।

बीजेपी का लक्ष्य देश के संविधान को खत्म करना : रामगोपाल

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रो.रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमले बोलते हुए कहा,बीजेपी का लक्ष्य केवल क्षेत्रीय दलों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि वह देश के संविधान को खत्म करने और देश को विखंडित (बांटने) का काम कर रही है. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। प्रो. रामगोपाल यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया और कहा कि हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से बीजेपी की धांधली रोकने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मौजूदा पार्टियों को तोड़ने पर भी बीजेपी की आलोचना की।

ममता बनर्जी ने जिन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया, वही दे रहे धोखा

पश्चिम बंगाल की राजनीति और तृणमूल कांग्रेस से पाला बदलने वाले नेताओं पर टिप्पणी करते हुए प्रो. यादव ने कहा, जिन लोगों को ममता बनर्जी ने कूड़ेदान के ढेर से उठाकर मंत्री, विधायक और सांसद बनाया, आज वही लोग उनके साथ विश्वासघात और धोखा कर रहे हैं।

27 में जान देकर भी धांधली रोकेंगे हमारे कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर प्रो. रामगोपाल यादव ने जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी और सत्ता पक्ष को चेतावनी देते हुए कहा, 027 में चुनाव हैं और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। अगर सत्ता पक्ष या अधिकारियों ने चुनाव में किसी भी तरह की धांधली करने की कोशिश की, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान देकर भी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और धांधली को नाकाम करेंगे।

ओबीसी समाज का वास्तविक हित बसपा ही चाहती है: मायावती

» विस-27 की चुनाव तैयारी में जुटीं बसपा प्रमुख

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । बहुजन समाज पार्टी प्रमुख ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पिछड़े वर्गों के बीच पहुंच बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही सामाजिक न्याय और विकास के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने वर्ष 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए ओबीसी समाज के बीच पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। लखनऊ में पिछले कई दिनों से चल रही बैठकों के दौरान उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि वर्ष 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनाने में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। पार्टी का प्रयास है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी उस सामाजिक गठजोड़ को फिर से मजबूत किया जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों के बीच यह संदेश पहुंचाएं कि ओबीसी समाज का वास्तविक हित और कल्याण बसपा तथा उसकी सरकारों में ही सुरक्षित रहा है। बैठक में मायावती ने आरोप लगाया कि अन्य राजनीतिक दलों ने समय-समय पर ओबीसी समाज का इस्तेमाल केवल चुनावी लाभ के लिए किया, लेकिन उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए। उन्होंने कहा कि बसपा ने अपनी स्थापना से लेकर सरकार में रहते हुए ओबीसी समाज को सम्मान और अधिकार दिलाने के लिए लगातार काम किया है। मायावती ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कराने में बसपा की भूमिका का भी उल्लेख किया। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज और नारायण गुरु जैसे महापुरुषों को सम्मान देने की पार्टी की नीति को सामाजिक परिवर्तन का आधार बताया।

भाजपा को रोकने के लिए विपक्ष से गठबंधन को तैयार: ओवैसी

» एआईएमआईएम नेता की पेशकश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि उनकी पार्टी 27 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को सत्ता में लौटने से रोकने के लिए दूसरे विपक्षी दलों के साथ गठबंधन करने को तैयार है। 16 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान, ओवैसी ने राज्य में एआईएमआईएम को पहले चुनावों में मिली हार को माना, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि पार्टी अब ज़मीनी स्तर पर ज़्यादा ज़ोर-शोर से प्रचार कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमने पिछली बार, 17 में चुनाव लड़ा था, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली... हम और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हमने अपनी पिछली गलतियों और कमियों को सुधारा है। अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले चुनावों की तैयारी के लिए राज्य पार्टी नेता शौकत अली और उनकी टीम को पूरे उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में 027 में चुनाव होने हैं, इसलिए हमारी पार्टी के नेता शौकत अली और पूरी टीम इसकी तैयारियों में जुटी हुई है। ओवैसी ने विपक्ष के वोट बंटने से बचाने के लिए बीजेपी-विरोधी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा भी जताई। इस दावे का जवाब देते हुए कि एआईएमआईएम धर्मनिरपेक्ष वोटों को बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, उन्होंने दूसरी विपक्षी पार्टियों के अंदर क्रॉस-वोटिंग के उदाहरण दिए, खासकर हालिया राज्यसभा चुनावों के दौरान, जहां कांग्रेस के तीन विधायकों और एआईएमआईएम के एक मुस्लिम विधायक ने अपनी ही पार्टियों का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने वहां जाकर कहा कि अगर बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए कोई गठबंधन बनता है, तो मैं तैयार हूं... हमारा मकसद यह पक्का करना है कि वहां से हमारे जो उम्मीदवार जीतें, वे विधायक बनें। यह बंटवारे का सवाल नहीं है। मैंने बिहार में भी यही बात कही थी कि हमारे साथ गठबंधन करें। हमारे अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने एक चिट्ठी भी लिखी थी। उसे नजरअंदाज कर दिया गया, और नतीजा आपने देखा ही। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस के तीन विधायकों और RJD के एक मुस्लिम विधायक ने उनका समर्थन नहीं किया।

एआईएमआईएम बीजपी की बी टीम : प्रियंका चतुर्वेदी

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) पर भी निशाना साधा और कहा कि ये पार्टी कुछ नहीं है, बीजेपी की बी टीम है। प्रियंका ने कहा यूपी की जनता समझदार है और सभी राजनीतिक चालों को समझती है. असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्यों हुई है, यूपी की जनता समझती है। ये एंट्री बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को मजबूत करने के लिए है जो फिलहाल कमजोर पड़ रही है और वोटरों का ध्यान भटकाने के लिए हुई है।

आरएसएस व बीजेपी ने शिलापूजन के नाम पर खूब पैसे वसूले: अजय

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ । यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, देश की आस्था के साथ बीजेपी-आरएसएस के द्वारा छल किया गया है। आज आस्था को बेचा जा रहा है और धर्म के नाम पर सौदा किया जा रहा है। श्रीरामजन्मभूमि को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है, वह दिखाती है कि एक संगठित लूट हुई है, जिसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं और ये बात खुद BJP के पूर्व सांसद कह रहे हैं।

श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट में एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नृपेंद्र मिश्रा को चेयरमैन बनाया गया, जो 5 साल 3 महीने तक नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव थे। यानी- इस संगठित लूट के जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ट्रस्ट में शामिल गोपाल राव पहले से ही विवादित रहे हैं। चंपत राय सारा माल लेकर चंपत हो गए। अनिल मिश्रा समेत संघ की पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ट्रस्ट में पद दिए गए थे। अब इस मामले में सरकार ने SIT गठित कर मान लिया है कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से गड़बड़ी हुई है।

राम मंदिर चढ़ावा मामला बहुत गंभीर: अनुप्रिया पटेल

» अपना दल की नेता ने कहा मंदिर साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मंदिर में चोरी अक्षम्य है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने राम मंदिर में चढ़ावे मामले पर कहा कि, ये बहुत गंभीर है और इसे राज्य सरकार ने संज्ञान ले लिया है। मामले की जाँच के लिए एसआईटी गठित की गई है. हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी हो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मंदिर के साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, मंदिर में चोरी अक्षम्य है।

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी अदिति पर अभद्र पोस्ट पर अनुप्रिया पटेल ने कहा कि हमारी लड़ाई है वो वैचारिक है, किसी का भी परिवार हो या बच्चा, किसी की भी बिटिया हो, हम सब परिवार के लोग हैं। हम किसी भी परिवार की बेटी के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी की घोर निंदा करते हैं. बेटियों को राजनीतिक लड़ाई में घसीटने की ज़रूरत नहीं है।

बीजेपी के काम आस्था नहीं केवल राजनीति : चतुर्वेदी

उबाठा नेत्री प्रियंका चतुर्वेदी ने राम मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित घोटाने पर कहा, इससे बड़ा पाप नहीं हो

सकता है कि आप श्रद्धालुओं का चढ़ावा अपनी जेबों में भरते हैं, एसआईटी की जांच में और खुलासे होंगे और ये जो उजागर हो रहा है, उससे भी बड़ा घोटाला सामने आयेगा। बीजेपी जो मंदिर का श्रेय लेती है, अब एक बड़े घोटाले में फंसी हुई है, जिससे पता चलता है कि उनके काम में आस्था या भक्ति नहीं है, ये केवल राजनीति करते हैं।

राम मंदिर चढ़ावे में धांधली बनेगा बीजेपी के लिए काल

विस-27 चुनाव से पहले विपक्ष को मिला बड़ा सवाल

सपा-आप व कांग्रेस ने बनाई सरकार को घेरने की योजना

» सपा प्रमुख अखिलेश हर मंच पर रहते हैं इसको लेकर मुखर

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। राम के नाम पर 17 व 22 में यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी 27 के विस चुनाव में उनके नाम पर लिए गए चंदे के हेरफेर में घिरती नजर आ रही है। 24 में लोकसभा की अयोध्या सीट हारने की टीस से न उबरने वाली भगवा पार्टी को लगता है 29 के चुनाव में एकबार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। सपा, आप, कांग्रेस समेत कई दलों ने भाजपा की डबलइंजन सरकार पर तीखा प्रहार जारी कर दिया है। खास तौर सपा प्रमुख व उनकी पार्टी इस मुद्दे को हर मंच उठाकर सरकार को घेर रही है।

मामला इतना बढ़ गया है कि इस पर राज्य सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी जांच को निगरानी में रख रहें है। राम मंदिर ट्रस्ट भी अपने स्तर से जांच में लगा हुआ है। इनसबके बीच मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। यूपी में 27 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी एक बार फिर बीजेपी को अयोध्या में फंसाने की कोशिश कर रही है। सपा चीफ बीजेपी को दोनों ओर से घेरने की रणनीति बनाते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव 27 से पहले भारतीय जनता पार्टी की हिन्दुत्ववादी सियासत की रणनीति को कमजोर करने की कोशिश शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि बीजेपी की इस रणनीति पर पलटवार की शुरुआत उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाकर की है। कुल मिलाकर राम मंदिर चढ़ावा विवाद ने अयोध्या की राजनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी और सरकार जांच के नतीजों का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें एसआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे विवाद का उत्तर प्रदेश की राजनीति और 27 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ता है। साथ ही बीजेपी की हिन्दुत्ववादी रणनीति पर अखिलेश की रणनीति, कितना सफल हो पाती है।

सपा के तेवर से घबराई पूरी भाजपा

अयोध्या का मुद्दा बीजेपी के लिए राजनीतिक और प्रतीकात्मक दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर उठे विवाद को सियासी बहस का विषय बनाकर सपा प्रमुख ने एक बार फिर बीजेपी को उसी मैदान में घेरने की कोशिश की है, जिसे पार्टी अपनी सबसे बड़ी वैचारिक और राजनीतिक उपलब्धियों में गिनती है। इस मामले में कन्नौज सांसद ने न सिर्फ सबसे पहले मुद्दा उठाया बल्कि जब विशेष जांच समिति गठित कर दी गई उसके बाद यह भी कह दिया कि बताओ अधिकारी जांच करेंगे हमारे भगवान के पुजारियों की? ये सनातन का अपमान है।

अयोध्या बीजेपी के लिए भावनात्मक मुद्दा

भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल और उनके नेता दावा करते रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना। हालांकि राम मंदिर के उद्घाटन और लोकार्पण के बाद चुनावों में बीजेपी को इसका सीधा लाभ मिलता नहीं दिखा। अयोध्या जिले में रुदौली, मिल्कीपुर (एससी), बीकापुर, अयोध्या और गोसाईंगंज विधानसभा सीट हैं। साल 22 के चुनाव में अयोध्या से बीजेपी के वेद प्रकाश, बीकापुर से अमित सिंह चौहान, रुदौली से रामचंद्र यादव और गोसाईंगंज से सपा के टिकट पर अभय सिंह (जो अब बीजेपी के साथ हैं) ने जीत हासिल की थी। वहीं मिल्कीपुर से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक चुने गए थे। यानी 22 में पांच में से तीन सीटों पर बीजेपी और दो सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। हालांकि आज के सियासी परिप्रेक्ष्य में पांचों सीटों पर बीजेपी का कब्जा है।

भाजपा नेता भी जांच के लिए पीएम को लिख रहे पत्र

उधर, अखिलेश यादव के आरोपों के बीच बीजेपी नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अगर जांच में किसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ही विपक्ष को जवाब देगी। अब जबकि इस मामले में सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव के आरोपों को निराधार बताते हुए जांच पूरी होने का इंतजार करने की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बाराबंकी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उन्हें सार्वजनिक किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एसआईटी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा : दिनेश शर्मा

इसके साथ ही बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अयोध्या राम मंदिर चंदे में हेराफेरी के आरोपों की तीन सदस्यीय एसआईटी जांच पर कहा, ये चोरी शब्द अच्छा नहीं है, जो भी विवाद है, उस पर लोग पारदर्शी तरीके से और समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, एसआईटी का गठन हो चुका है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है, जो एसआईटी का निर्णय आएगा, वह देखा जाएगा। इसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

उपचुनाव में मिल्कीपुर ने दी थी राहत!

लोकसभा चुनाव के करीब 10 महीने बाद फरवरी 25 में अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने वापसी की। फैजाबाद सांसद और सपा नेता अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हराकर बीजेपी के चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की। इस जीत के बाद बीजेपी ने राहत की सांस ली थी। हालांकि सपा प्रमुख आज भी कई मौकों पर मिल्कीपुर उपचुनाव में कथित धांधली के आरोप लगाते रहे हैं।

साल 24 में लगा था बीजेपी को झटका

साल 24 में अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण हुआ, उसी साल करीब तीन महीने बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी न सिर्फ 2014 और 19 के मुकाबले कम सीटों के साथ लोकसभा में पहुंची बल्कि फैजाबाद लोकसभा सीट भी हार गई। सपा के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को पराजित कर दिया। हालांकि चुनाव परिणामों के बाद बीजेपी और उसके नेता यह कहकर खुद को तसल्ली देते रहे कि भले ही पार्टी फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई हो, लेकिन अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में उसे बढ़त मिली थी।

7 जून दोपहर को सपा चीफ ने अयोध्या मामले पर सबसे पहला पोस्ट किया

7 जून दोपहर को सपा चीफ ने अयोध्या मामले पर सबसे पहला पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया था, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए ये एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि 'राम मंदिर' के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। उसके बाद फिर अखिलेश ने 7 जून को ही देर रात एक पोस्ट किया, जिसमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और महासचिव के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा था - चेहरे के भाव और देह की भाषा हताशा और निराशा से भरी है। अखिलेश ने राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर लगाए गए अपने आरोपों पर स्पष्टीकरण आने के बाद 9 जून को 11 सवाल भी पूछे। अपने इन सवालों में कन्नौज सांसद ने पूछा था- डबल इंजन क्या सिर्फ डबल ईंधन का उपभोग करने के लिए हैं या उनकी कोई जिम्मेदारी भी है? अपने इस सवाल के जरिए अखिलेश, राम मंदिर के बहाने, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और यूपी की राज्य सरकार को निशाना बनाने की कोशिश करते दिखे। इसी दिन देर रात एक पोस्ट में अखिलेश ने पूछा था- सरकार मौन क्यों है? क्या जांच की आंच से बड़े लोग डरे हुए हैं? करीब चार दिन बाद 13 जून को अखिलेश ने फिर लिखा। अखिलेश का यह पोस्ट एसआईटी गठित होने के बाद आया। इसमें उन्होंने लिखा कि यदि दोषी के बारे में पता करने में पुलिस अक्षम है तो हम सहायता कर दें। फिर 14 जून को अखिलेश ने आगरा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा- प्रभु श्रीराम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लें। जो चढ़ावा चोरी हुआ है वो वापस कर दें। अधिकारी जांच करेंगे हमारे पुजारियों की? यह सनातन धर्म का अपमान है। कोई इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

बाल श्रम के खिलाफ आवाज को बुलंद करे समाज

गत दिनों पूरी दुनिया में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। इसका मकसद बाल मजदूरी रोकना हैं। पर अफसोस विश्व श्रम संगठन जो यून की एक संस्था है इसकी जागरूकतका के बाद भी ये कुरीति भारत जैसे देशों में आज भी विकराल रूप में जारी है। सरकारों के साथ समाज के सहयोग से ही ये व्यवस्था सुधर पाएगी और बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता हैं। जनगणना 11 के अनुसार भारत में 5-11 वर्ष आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन थी जिसमें 10 मिलियन से अधिक यानी 4 फीसदी आबादी बाल श्रमिकों की पाई गई थी। आज 26 में 146 करोड़ आबादी में इन आंकड़ों पर गौरफरमाते हैं तो ये आंकड़े काफी बढ़े दिखाई देते हैं। 'बालश्रम' समस्या दशकों से न सिर्फ भारत में, बल्कि समूचे संसार में प्रचलित रही है। वैसे, बालश्रम अपने आप में किसी कलंक से कम नहीं? भारत की बात करें, तो लाखों की संख्या में नौनिहाल विभिन्न राज्यों में किसी न किसी मजबूरी के चलते अपने जीवन को श्रम की भट्टियों में झुका हुआ है। हालांकि, सरकारी और सामाजिक स्तर पर रोकने की कोशिशों में कोई कोर-कसर नहीं? पर, समस्या घटने के जगह बढ़ ही रही है दिनोंदिन। आज 'विश्व बाल श्रम निषेध दिवस' है जो सालाना 12 जून को मनाया जाता है।

इसकी शुरूआत वर्ष-2002 में 'अंनराष्ट्रीय श्रम संगठन' की अगुआई में बड़े वैचारिक स्तर पर मुकर्रर की गई थी। दिवस का आज 24वीं संस्करण पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मकसद, चाइल्ड लेबर के विरूद्ध वैश्विक मंचों पर ईमानदारी से जागरूकता फैलाना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर जनमानस को आहवान करना। कानून और संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित है। बावजूद इसके गरीब, अक्षम और असहाय बच्चों के साथ असमानता और भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के मुताबिक किसी भी कर-कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी चोरी-छिपे बच्चों से काम करवाया जाता है। ये बात शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन के लोग भी भली भांति जानते हैं। लेकिन कार्रवाई के जगह अपनी आंख मूंदे रहते हैं। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने साल-1986 में बाल श्रम के विरूद्ध रोकथाम के लिए कठोर अधिनियम बनाया था जिसके तहत बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे खादानों, मशीनरी कारखानों में जबरन काम करवाने वालों पर दंडनीय अपराध का प्रावधान तय किया था। लेकिन इस कठोर कानून की भी खुलआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं। अब समय आ गया है दुनिया का हर एक व्यक्ति बाल श्रम के खिलाफ आवाज को बुलंद करे।

'बालश्रम' समस्या दशकों से न सिर्फ भारत में, बल्कि समूचे संसार में प्रचलित रही है। वैसे, बालश्रम अपने आप में किसी कलंक से कम नहीं? भारत की बात करें, तो लाखों की संख्या में नौनिहाल विभिन्न राज्यों में किसी न किसी मजबूरी के चलते अपने जीवन को श्रम की भट्टियों में झुका हुआ है।

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

एसआईआर की तार्किकता और विरोध का प्रश्न

प्रमोद जोशी

हाल ही में 'इंडिया' गठबंधन ने पांच-सूत्री प्रस्ताव पारित किया, जिसमें एक यह भी है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा जाएगा। यह गठबंधन 'एसआईआर' को 'वोट चोरी' मानता है। इसके कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने 'एसआईआर' को लेकर चुनाव-आयोग को क्लीन-चिट दी है। प्रश्न है कि ऐसे में पत्र लिखने से मिलेगा क्या? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है, हम इसे 'वोट लूट' की कोशिश मानते हैं। भारत में घुसपैठ और नागरिकता रजिस्टर पिछले कई दशकों से बहस में हैं। यह बहस अब मतदाता सूची की बहस के साथ जुड़ गई है। 'एसआईआर' के देश में दो दौर हो चुके हैं और तीसरा शुरू हो गया है। पहला दौर मुख्यत: बिहार-केंद्रित था, जो जून से सितंबर, 2025 तक चला।

27 अक्टूबर से दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत, नौ राज्य और तीन केंद्र-शासित क्षेत्र शामिल थे। गत 14 मई को निर्वाचन आयोग ने 'एसआईआर' के तीसरे दौर की भी घोषणा कर दी, जिसमें सोलह राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों को कवर किया गया है। इसके पूरा होने के बाद जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके साथ इस प्रक्रिया को बहस नए सिरे से शुरू होगी, जिसकी अनुगूंज संसद के मॉनसून सत्र में सुनाई पड़ेगी। शिकायतें पहले दौर के पहले से ही शुरू हो गई थीं, पर पश्चिम बंगाल का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौर में करीब 27 लाख वोटरों ने अपने नाम कटने को चुनौती दी। वे विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए नियुक्त न्यायाधिकरण इस काम को पूरा नहीं कर पाए। यह काम चुनाव परिणाम आने के बाद भी चल ही रहा है। इन 27 लाख में 60 प्रतिशत से ज्यादा वोटरों की सूची में वापसी हो चुकी है और अंतिम समाचार मिलने तक न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया जारी है। सवाल है कि उनकी सुनवाई के लिए नागरिक-प्रशासन पर राज्य सरकार ने भरोसा क्यों नहीं किया?

चुनाव-आयोग की व्यवस्था है कि 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के कारण कोई नाम 'अनमैप्ड' रह जाए, तो एक सूची में वर्णित दस्तावेजों में से कोई एक देकर अपने नाम को बनाए रखा जा सकता है। पर बंगाल में अविश्वास इतना गहरा था कि उस रास्ते पर जाने के बजाय लंबे रास्ते को अपनाया गया, जिसकी वजह

से बड़ी संख्या में लोग वोट नहीं दे पाए। कई तरह के सवाल सभी पक्षों से हैं। आयोग ने सूची के गहन-संशोधन के लिए पर्याप्त समय क्यों नहीं दिया? 2002 और 2003 की मतदाता सूचियों तक पहुंच पाना आसान काम नहीं है। पुरानी सूचियां जिस तरीके से बनाई गईं हैं, उनमें नाम, पते और वोटर कार्ड की संख्या खोजना खासा मुश्किल काम है। सामान्य नागरिक कागज-पत्रों के आदी नहीं हैं, उनके लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं है। देश की आम जनता दस्तावेजों की अभ्यस्त नहीं है। 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' को दूर करने के लिए दस्तावेजों को भी आसान बनाने की जरूरत है। वोटर को पुरानी सूची में अपना नाम खोजने में दिक्कत होती है। उसकी मदद की जानी चाहिए। आयोग की वेबसाइट को सरल बनाने और इस काम को करने वाले बीएलओ को बेहतर तरीके से तैयार करने की जरूरत भी है। विरोधी-दलों ने इसे 'वोट चोरी' साबित करते हुए, राजनीतिक सवाल बनाया। चुनाव-आयोग, उसकी प्रक्रिया और ईवीएम की साख पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बात को उन्हें सुप्रीम कोर्ट में साबित करना होगा। जब उन्हें विजय मिलती है, तब वे सवाल करते, क्यों नहीं करते? दिसंबर में लोकसभा में चुनाव-सुधारों पर हो रही बहस के दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, 'मैं इसी मशीन से चुनकर आई हूं, इसलिए मैं ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाऊंगी।' सवाल हैं भी, तो उन्हें या तो आयोग और या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाना चाहिए। पर अब तो अदालती फैसलों पर भी संदेह पैदा किया जाता है। कहा जा रहा है कि आयोग को 'एसआईआर' कराने का अधिकार है ही नहीं। फिर मतदाता सूची में संशोधन या सुधार कैसे होगा? सोशल मीडिया के शोर ने स्थितियों को और बिगाड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने अब 27 मई को याचिकाकर्ताओं के ज्यादातर तर्कों को मानने से इनकार कर दिया।

वहीं चुनाव-आयोग के तर्कों को स्वीकार किया और उन्हें और स्पष्ट किया। हालांकि यह मामला बिहार में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के नियम को लागू करने से संबंधित था, लेकिन अदालत में विचारार्थ रखे गए मुद्दे और उसके निष्कर्ष देश भर की मतदाता सूचियों में नाम दर्ज कराने के अधिकार पर दूरगामी प्रभाव डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि आयोग का संवैधानिक दायित्व है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे।

राष्ट्र निर्माण की अदृश्य आधारशिला का मूल्यांकन

डॉ. रितु सारस्वत

हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने 'शिशुपाल उर्फ शिशराम एवं अन्य बनाम सुरजीत एवं अन्य' मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए भारतीय समाज के समक्ष उपस्थित एक ऐसे प्रश्न को पुन: केंद्र में ला खड़ा किया है, जिस पर लंबे समय से पर्याप्त गंभीरता से विचार नहीं किया गया। न्यायालय ने गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' की संज्ञा देते हुए कहा कि उनके द्वारा किया जाने वाला घरेलू श्रम केवल परिवार के संचालन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। न्यायालय ने निर्देश देते हुए कहा कि 'जब कोई मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, उच्च न्यायालय अथवा यह न्यायालय किसी ऐसे मामले पर विचार कर रहा हो, जिसमें एक गृहिणी की मृत्यु हुई हो, तब मुआवजे की गणना में गृहिणियों के साथ होने वाली उस अंतर्निहित असमानता को दूर करने के लिए, जो उनकी अनुमानित आय के अत्यंत रूढ़िवादी आकलन के कारण उत्पन्न होती है, 'घरेलू देखभाल की हानि' के अंतर्गत 30,000 रुपये प्रतिमाह की एक समेकित राशि जोड़ी जानी चाहिए।'

न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस राशि में प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर संचयी रूप से 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। प्रथम दृष्टया यह निर्णय मोटर दुर्घटना मुआवजा दावों में क्षतिपूर्ति निर्धारण से संबंधित एक सामान्य न्यायिक आदेश प्रतीत हो सकता है, किन्तु वास्तव में इसका महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह निर्णय केवल 30,000 रुपये प्रतिमाह की राशि निर्धारित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस दृष्टिकोण में परिवर्तन का प्रतीक है, जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने घरेलू श्रम के सामाजिक और आर्थिक मूल्य को स्वीकार किया है। लंबे समय तक भारतीय समाज में घर के भीतर किए जाने वाले कार्यों को प्रेम, कर्तव्य और पारिवारिक दायित्व के रूप में देखा जाता रहा, जबकि उनके आर्थिक महत्व पर अपेक्षित गंभीरता से विचार नहीं किया गया। निस्संदेह, किसी भी परिवार का सुचारु संचालन केवल आर्थिक आय पर निर्भर नहीं करता।

भोजन की व्यवस्था, बच्चों का पालन-पोषण, वृद्धजनों की देखभाल, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं का समन्वय, घर का प्रबंधन तथा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने जैसे असंख्य कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं, जिनके लिए कोई वेतन निर्धारित नहीं होता। विडंबना यह है कि जिन कार्यों के बिना परिवार की संरचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही कार्य लंबे समय तक आर्थिक मूल्यांकन की प्रक्रिया से बाहर रहे। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि 'यह विडंबनापूर्ण है कि गृहिणी को परिवार के कमाने वाले सदस्यों पर आश्रित बताया जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि परिवार की पूरी व्यवस्था और सुचारु संचालन काफी हद तक गृहिणी पर ही निर्भर करता है।' वास्तव में यह टिप्पणी भारतीय समाज में लंबे समय से प्रचलित उस धारणा को चुनौती देती है, जिसके अनुसार आर्थिक आय अर्जित करने वाला व्यक्ति ही परिवार का मुख्य योगदानकर्ता माना जाता है। यदि किसी परिवार की आय उसके आर्थिक आधार को सुदृढ़ करती है, तो घर के भीतर किया जाने वाला श्रम उस आधार को स्थायित्व प्रदान करता है।

दोनों में से किसी एक के अभाव में परिवार की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए घरेलू श्रम को केवल एक पारिवारिक दायित्व मानना उसके वास्तविक महत्व को कम करके आंकना होगा। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया कि 'गृहिणियों का योगदान केवल बच्चों के जन्म और पालन-पोषण तक सीमित नहीं है। वे उस मानव पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिस पर किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति आधारित होती है।' यह निर्विवादित है कि किसी भी समाज का भविष्य केवल उसके उद्योगों, संस्थानों अथवा आर्थिक नीतियों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन मानवीय मूल्यों, संस्कारों और क्षमताओं से भी निर्मित होता है, जिनका विकास परिवार के भीतर होता है। वर्तमान निर्णय का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्षतिपूर्ति निर्धारण के संबंध में विकसित हो रहे न्यायशास्त्र को भी आगे बढ़ाया है। इस संदर्भ में न्यायालय ने 'नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य' के ऐतिहासिक निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें क्षतिपूर्ति निर्धारण के लिए कुछ पारंपरिक मदों, जैसे संपत्ति की हानि, साहचर्य की हानि तथा अंत्येष्टि व्यय को मान्यता प्रदान की गई थी।

'शिशुपाल उर्फ शिशराम एवं अन्य बनाम सुरजीत एवं अन्य' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टिकोण का विस्तार करते हुए 'घरेलू देखभाल की हानि' को भी एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में स्वीकार किया है। यह परिवर्तन केवल विधिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत अर्थपूर्ण है। किसी गृहिणी की मृत्यु के पश्चात परिवार को केवल भावनात्मक आघात ही नहीं पहुंचता, बल्कि वर्षों से संचालित हो रही देखभाल, मार्गदर्शन, संरक्षण और घरेलू प्रबंधन की वह व्यवस्था भी प्रभावित होती है, जिसका कोई प्रत्यक्ष आर्थिक मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता। न्यायालय ने वस्तुत: इसी अदृश्य हानि को पहचानने और उसका न्यायसंगत मूल्यांकन करने का प्रयास किया है। न्यायालय ने स्वीकार किया कि महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक घरेलू एवं देखभाल संबंधी कार्य का आर्थिक मूल्य भारत की सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 15 से 17 प्रतिशत के समतुल्य आंका गया है।

डायबिटीज और तनाव में फायदेमंद है गोमुखासन

योग स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली बनाए रखने का प्राकृतिक तरीका है। शरीर की जकड़न, कंधों और पीठ का दर्द आम समस्या है, जो अधिकतर लोगों को रहता है। इन स्वास्थ्य समस्याओं से राहत पाने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित गोमुखासन का अभ्यास करना चाहिए। गोमुखासन एक सरल लेकिन प्रभावशाली योगासन है, जो शरीर और मन दोनों के लिए फायदेमंद है। सही तकनीक और सावधानियों के साथ नियमित अभ्यास करने से आपको बेहतर लचीलापन, कम तनाव और मजबूत मांसपेशियां मिल सकती हैं। गोमुखासन दो शब्दों से मिलकर बना है, गो यानी गाय और मुख यानी चेहरा। इस आसन में शरीर की आकृति गाय के चेहरे जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है।

करने का सही तरीका

योगासन में से एक गोमुखासन करने का तरीका बेहद आसान है। इस योगासन को करने के लिए दरी या योगा मैट पर सीधे बैठ जाएं और पैरों को सामने फैलाएं। अब दाएं पैर को मोड़कर बाएं कूल्हे के नीचे रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के ऊपर रखें, ताकि दोनों घुटने एक-दूसरे के ऊपर दिखें। दायां हाथ ऊपर उठाएं और कोहनी मोड़कर पीठ के पीछे ले जाएं। बायां हाथ पीछे से ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में पकड़ें। पीठ सीधी रखें और 20-30 सेकंड तक सामान्य श्वास लेते रहें। धीरे-धीरे सामान्य अवस्था में लौटें और दूसरी ओर से दोहराएं। सुबह खाली पेट करना बेहतर होता है। 2-3 बार दोहरा सकते हैं। अगर आप सही तरीके से गोमुखासन करते है तो इसका फायदा उन्हें मिलता है। शुरुआत में अगर हाथ पीठ पर नहीं मिल पाते तो रुमाल या पट्टी की मदद ली जा सकती है। कंधे या घुटने की गंभीर चोट वाले लोगों को डॉक्टर या योग प्रशिक्षक की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

अंदरूनी अंगों को बेहतर करता है

नियमित अभ्यास पैंक्रियाज को सक्रिय करने में मदद कर सकता है। यह आसन मन को शांत कर मानसिक तनाव घटाने में मदद करता है। डायबिटीज के मरीजों को भी गोमुखासन करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह योगासन शरीर के अंदरूनी अंगों पर बेहतरीन असर डालता है। इसे करने से ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है और पाचन तंत्र भी बेहतर होता है। इसके साथ ही यह हार्ट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि इसे करने से तनाव कम होता है, जिससे दिल पर दबाव नहीं पड़ता और ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है। छाती खुलने से सांस लेने की क्षमता बेहतर होती है। इसके अलावा इसके अभ्यास से साइटिका को ठीक करता है। हाई ब्लड प्रेशर में मदद करता है। खराब मुद्रा वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है।

सावधानियां

अगर कंधे या घुटने में गंभीर दर्द है तो यह आसन न करें। स्लिप डिस्क या रीढ़ की गंभीर समस्या होने पर डॉक्टर की सलाह लें। शुरुआत में ज्यादा जोर न लगाएं। गर्भावस्था में विशेषज्ञ की देखरेख में ही अभ्यास करें।

कंधों और पीठ के दर्द में राहत

यह आसन कंधों की जकड़न दूर करता है और सर्वाइकल या पीठ दर्द में आराम देता है। यह आसन शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, खासकर कंधे, पीठ और जांघों की मांसपेशियों पर ज्यादा असर डालता है। गोमुखासन सर्वाइकल की समस्या में भी फायदेमंद होता है, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को सीधा और मजबूत बनाता है। कमर दर्द में भी इससे राहत मिलती है। जांघ, कूल्हे और हाथों की मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं। पीठ में दर्द वैसे तो एक बेहद आम समस्या है लेकिन लापरवाही इस तरह के दर्द को लाइलाज भी बना सकती है। गलत तरीके से खड़ा होना, ज्यादा देर तक एक जगह बैठे रहना ऐसी वजहों से स्थिति खराब हो सकती है।

हंसना मना है

पचास वर्षीय-पति-'आज सवेरे शेव करने के पश्चात मैं महसूस कर रहा था कि मेरी उम्र के दस साल कम हो गए।' पत्नी-'क्या कहते हो! अगर इस स्पीड से प्रतिदिन आयु कम होती चली गई, तो एक हफ्ते में आप गायब ही हो जाओगे।

लड़का लाइब्रेरी से 'बच्चों का पालन-पोषण की पुस्तक लेकर आया।' उसकी मां ने आश्चर्य से पूछा-'क्यों मुन्ने, इस पुस्तक का क्या करोगे? मुन्ने ने जबाब दिया-'मैं इसे पढ़कर ये जानना चाहता हूं कि मेरा पालन-पोषण उचित ढंग से किया जा रहा है की नहीं।'

पत्नी-'मैं तुमसे जो भी कहती हूं आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो।' पति-'किन्तु मैं भी जो कहता हूं आप उसे दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती हो।'

सुरेश-'अरे प्रकाश! हाथ में चोट कैसे लगी।' प्रकाश-'मैंने गाय के दांत गिनने के लिए उसके मुंह में हाथ डाला। उसने मेरी उंगली गिनने के लिए मुंह बन्द कर लिया।'

एक इंसान (दूसरे से)-'आ जाओ, कुत्ते से डरो नहीं।' पहला व्यक्ति-'क्यों, आपका कुत्ता काटता नहीं?' दूसरा व्यक्ति-'यही देखने के लिए तो आपको बुलाया है।'

कहानी | जीवन के बाद का प्रकृति नियम

एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले कि नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले कि भैया! बड़े जोरों की भूख लगी है। थोड़ा सा खाना मिल जाएगा। सेठ जी बिगड़कर बोले कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती। तुम्हारे बाप का माल है? कर्म करके खाने में शर्म आती है, जाओ-जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले- देखा प्रभु ! यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है। इसको अभी शाप दीजिये। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन सम्पति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर में गए। जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगायी, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आयी। दोनों सन्तों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दुध लेकर आयीं और बोली- प्रभु मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिये। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा- प्रभु आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मुझसे तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है। आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा- प्रभु जी! यह आपने क्या किया? भगवान बोले- यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है। कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिन्ता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिन्ता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरने वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है जिस चीज में अति लगाव रहेगा यह जीव मरने के बाद वही जनम लेता है और बहुत दुख भोगता है, अत: अपना चिंतन प्रभू की तरफ अधिक रखे।

7 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से सहयोग प्राप्त होगा। पूजा-पाठ में मन लगेगा। तीर्थदर्शन हो सकते हैं। विवेक का प्रयोग करें, लाभ होगा।

वृषभ

स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। चोट व दुर्घटना से हानि संभव है। कार्य करते समय लापरवाही न करें। बनते कामों में बाधा हो सकती है। विवाद से बचें।

मिथुन

घर-परिवार की चिंता रहेगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। घर-परिवार में प्रसन्नता रहेगी। बाहर जाने का मन बनेगा।

कर्क

लेन-देन में जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तु समय पर नहीं मिलने से क्रोध रहेगा। भूमि व भवन संबंधी बड़े सौदे बड़ा लाभ दे सकते हैं। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

सिंह

रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यात्रा मनोरंजक रहेगी। पार्टी व पिकनिक का आनंद मिलेगा। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

कन्या

बुरी सूचना मिल सकती है। मेहनत अधिक होगी। स्वास्थ्य का पाया कमजोर रहेगा। आय में कमी रहेगी। नकारात्मकता बढ़ेगी। विवाद से क्लेश होगा।

तुला

सामाजिक कार्यों में मन लगेगा। दूसरों की सहायता कर पाएंगे। मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। पारिवारिक सहयोग मिलेगा। व्यापार ठीक चलेगा।

वृश्चिक

उत्साहवर्धक सूचना प्राप्त होगी। भूले-बिसरे साथियों से मुलाकात होगी। कोई नया बड़ा काम करने की योजना बनेगी। भाइयों का सहयोग प्राप्त होगा।

धनु

किसी बड़ी समस्या का हल मिलेगा। व्यावसायिक साझेदार पूर्ण सहयोग करेंगे। कोई नया उपक्रम प्रारंभ करने का मन बनेगा। सेहत का ध्यान रखें।

मकर

सेहत को प्रा?थमिकता दें। लेन-देन में जल्दबाजी से हानि होगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय नहीं है। चिंता तथा तनाव रहेंगे।

कुम्भ

आय में वृद्धि होगी। बिगड़े काम बनेंगे। प्रसन्नता रहेगी। मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। व्यस्तता के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखें।

मीन

मान-सम्मान मिलेगा। व्यापार मनोनुकूल चलेगा। योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन संभव है। विरोध होगा। काम करते समय लापरवाही न करें।

हालीवुड | रिलीज डेट

शुरू में मुझे भी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था : माधुरी दीक्षित

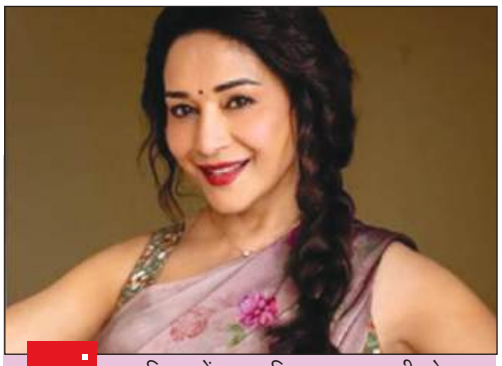

मां बहन फिल्म में उनका किरदार समाज की सोच और जजमेंट का सामना करता है, खासकर उनके स्लीवलेस ब्लाउज पहनने को लेकर। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में माधुरी ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें भी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा था। माधुरी ने बताया कि एक पब्लिक फिगर होने के नाते लोगों की राय और कमेंट्स से बचना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा, 'जब मैंने करियर शुरू किया था, तब लोग कहते थे कि मैं बहुत पतली हूं। लोग कहते थे- इसको कुछ खिलाओ। लोग बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। अगर आपका वजन बढ़ जाए तो भी बोलेंगे, कम हो जाए तो भी बोलेंगे।' माधुरी ने यह भी कहा कि पहले के समय में ऐसी बातों से निपटना थोड़ा आसान था क्योंकि तब सोशल मीडिया नहीं था। उन्होंने कहा, 'आज के समय में सोशल मीडिया और उसकी अनाम पहचान की वजह से लोग कुछ भी कह देते हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अपने काम पर ध्यान दें, जो आपको पसंद है वही करें और खुद से प्यार करना सीखें।' माधुरी दीक्षित ने 1980 के दशक में फिल्म 'अबोध' (1984) से अपने करियर की शुरुआत की थी। शुरुआत में उनकी कई फिल्में नहीं चलीं और उन्हें इंडस्ट्री में जगह बनाने में समय लगा। उनकी किस्मत बदली फिल्म 'तेजाब' (1988) से, जिसमें उनके साथ अनिल कपूर नजर आए। इस फिल्म का गाना 'एक दो तीन' बेहद हिट हुआ और माधुरी रातों-रात स्टार बन गईं। इसके बाद उन्होंने 'राम लखन', 'दिल' और 'साजन' जैसी कई हिट फिल्मों से खुद को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया।

कार्तिक आर्यन की फिल्म में शरवरी वाघ की हुई इंट्री

बॉलीवुड | गपशप

कार्तिक आर्यन का नाम उनकी कई अपकमिंग मूवीज को लेकर चर्चा में बना हुआ है। अब खबर आ रही है कि कार्तिक की एक नई फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन कर रहे हैं। कार्तिक और लव की इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस की तलाश जारी है। इस बीच बी टाउन इंडस्ट्री की एक पॉपुलर एक्ट्रेस का नाम इस रेस में शामिल है। ये एक्ट्रेस बनेगी कार्तिक की हीरोइन इन दिनों अभिनेत्री शरवरी वाघ के सितारे बुलंदी पर चल रहे हैं। एक तरफ वह अपनी हालिया प्रदर्शित फिल्म मैं वापस आऊंगा के लिए प्रशंसा बटोर रही हैं तो दूसरी तरफ अगले महीने उनकी फिल्म अल्फा भी प्रदर्शन की कतार में है। सूरज बड़जात्या निर्देशित और आयुष्मान खुराना अभिनीत फिल्म ये प्रेम मोल लिया भी इसी साल प्रदर्शित होगी। इस बीच खबरें हैं कि अब वह कार्तिक आर्यन के साथ भी फिल्म करने जा रही हैं। दरअसल, कार्तिक जल्द ही लव रंजन के निर्देशन में बन रही रोमांटिक कामेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म की नायिका की भूमिका के लिए लव ने शरवरी से संपर्क किया है। शरवरी ने भी इस फिल्म में दिलचस्पी दिखाई है। फिलहाल लव इस फिल्म की पटकथा पर काम कर रहे हैं। उनकी योजना दिसंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की है। पटकथा पूरी होने के बाद वह कार्तिक और शरवरी को पूरी पटकथा सुनाएंगे। उसके बाद शरवरी फिल्म पर अपना अंतिम निर्णय लेंगी। वहीं कार्तिक आगामी दिनों में नागजिला और अनुराग बासु निर्देशित अनाम फिल्म में नजर आएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो कार्तिक और शरवरी की जोड़ी पहली बार हिंदी सिनेमा में दिखेगी। यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड मूवी अल्फा में शरवरी वाघ का अहम किरदार होने वाला है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में शरवरी इंडियन स्पाई एजेंट के रोल में नजर आएंगी। उनकी ये फिल्म 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अल्फा में शरवरी के अलावा आलिया भट्ट, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे कलाकार भी मौजूद हैं।

अब रियल्टी शो होस्ट करेंगे कुणाल खेमू

कुणाल खेमू जल्द ही रियलिटी शो होस्ट के रूप में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। वह नई सीरीज़ अलायंस को होस्ट करेंगे, जो 26 जून से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अलायंस, जॉन डी मोल द्वारा निर्मित और वैश्विक स्तर पर प्रशंसित टाल्पा स्टूडियोज के डच फॉर्मेट का पहला अंतरराष्ट्रीय रूपांतरण है। इस हिंदी रियलिटी शो को बनिजे एशिया ने प्रोड्यूस किया है।

शुरुआत में तो सहयोगी के रूप में प्रवेश करेंगे, लेकिन अंतिम पुरस्कार (विजेता ट्रॉफी) की इस होड़ में बदलती वफादारी, आपसी छल और रणनीतिक दांव-पेच हर गठबंधन की कड़ी परीक्षा लेंगे। बनिजे एशिया के फाउंडर और ग्रुप सीईओ दीपक धर ने एक बयान में कहा, शो का नाम देखते हुए, यह कहना सही होगा कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए प्राइम वीडियो के साथ जुड़कर बहुत उत्साहित हैं। इस फॉर्मेट की जिस बात ने हमें आकर्षित किया, वह थी इसका विशाल पैमाना। इसके गेम्स बड़े और सिनेमैटिक हैं और ऐसे हैं, जो हमने पहले कभी नहीं किए।

उनके मुताबिक,सिर्फ़ दिखावे से कोई फ़ॉर्मेट शानदार नहीं बनता। अलायंस को जो चीज़ खास बनाती है, वह है रणनीति और परफॉर्मेंस के बीच लगातार चलने वाला तालमेल। इसमें कंटेस्टेंट्स को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से चुनौती दी जाती है और हर चुनौती नए मौके और नई मुश्किलें लेकर आती है। यह फ़ास्ट, अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही डायनामिक है। प्राइम वीडियो इंडिया के ओरिजिनल्स के डायरेक्टर और हेड निखिल मधोक ने कहा, हम देश भर के दर्शकों के लिए अलायंस लाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं। भारत के लिए अपनी तरह के इस पहले फॉर्मेट में अलायंस में स्ट्रैटेजी, बदलती वफ़ादारी और लगातार बदलते गेमप्ले का मेल होगा। यह एक ऐसा शानदार अनुभव देगा जो शुरू से आखिर तक हर दिन दर्शकों को बांधे रखेगा।

अजब-गजब | यहां ज्यादातर लोग बोलते हैं भोजपुरी, दिवाली पर मिलती है छुट्टी!

भारत से 13 हजार किमी. दूर बसा है एक और इंडिया!

क्या आप जानते हैं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश है जहां आपको भारत जैसा माहौल मिलेगा? दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में स्थित गयाना को लोग 'मिनी इंडिया' कहते हैं। यहां भारतीय संस्कृति, भाषा, त्योहार और परंपराएं आज भी जीवित है। 13 हजार किलोमीटर दूर भारत की छाप भारत से गयाना की दूरी लगभग 13000 से 14,000 किलोमीटर है। फिर भी यहां 40 प्रतिशत से अधिक आबादी भारतीय मूल की है।

19वीं सदी में ब्रिटिश काल में उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य इलाकों से हजारों भारतीय मजदूरों को चीनी के खेतों में काम करने के लिए इंडेंटर्ड लेबर सिस्टम के तहत यहां लाया गया था। 1838 से शुरू हुए इस सिलसिले में करीब 2,38,000 भारतीय गयाना पहुंचे। इसके बाद ये लोग वापस लौटने की जगह यही बसते चले गए। आज उनके वंशज गयाना की सबसे बड़ी जनसंख्या का हिस्सा हैं।

गयाना में ज्यादातर इंडो-गयानी लोग भोजपुरी, अवधी और हिंदी के मिश्रित रूप में बात करते हैं। अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है, लेकिन घरों में भोजपुरी बोली बहुत आम है। कई शब्द आज भी शुद्ध हिंदी या भोजपुरी जैसे लगते हैं। लोक गीत, रामलीला और कहानियां भारतीय परंपरा को जीवित रखती हैं। इसके अलावा यहां दिवाली नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। गयाना में दिवाली को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया है। पूरे देश में दीये जलाए जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, मिठाइयां बांटी जाती हैं। होली, फगवा, रामनवमी और अन्य भारतीय त्योहार भी यहां बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। हिंदू मंदिरों की संख्या अच्छी-खासी है और भारतीय संस्कृति को सम्मान मिलता है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार गयाना की कुल आबादी में 39.8 प्रतिशत लोग इंडो-गयानी हैं। ये लोग राजनीति, व्यापार, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति चेद्दी जगन और कई अन्य प्रमुख नेता भारतीय मूल के रहे हैं। गयाना में भारतीय संस्कृति अफ्रीकी, इंडियन, अमेरिंडियन और यूरोपीय संस्कृतियों के साथ घुल-मिल गई है। फिर भी भारतीय पहचान मजबूत बनी हुई है। लोग घर पर भारतीय व्यंजन बनाते है, जिसमें दाल-चावल, करी, रोटी, आलू-परवल आदि शामिल है। साथ ही शादियों में भारतीय रीति-रिवाजों का पालन होता है।

गयाना हाल के वर्षों में तेल की खोज के बाद आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ा है। इंडो-गयानी समुदाय इस विकास में अहम योगदान दे रहा है। हालांकि चुनौतियां भी हैं, लेकिन सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के प्रयास लगातार जारी है।

भारत में होते हुए भी विदेश में है ये गांव पासपोर्ट दिखाने पर ही होती है एंट्री

अगर आप भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाएंगे तो आपको पासपोर्ट या वीजा की जरुरत पड़ती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि भारत के अंदर ही एक ऐसी जगह है, जहां भारतियों को सीधे एंट्री नहीं है तो आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं लेकिन ऐसा सच में है। आज भी भारत की सरजमीं पर एक ऐसा इलाका है जहां जाने के लिए भारतीयों को पासपोर्ट जैसी अनुमति या स्पेशल परमिट लेना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले में स्थित तीन बीघा कॉरिडोर और दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव की, जो भारत में है, लेकिन यहां की व्यवस्था बांग्लादेश के नियंत्रण में है। तीन बीघा कॉरिडोर मात्र 178 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा एक कॉरिडोर है। 1996 में भारत सरकार ने इसे बांग्लादेश को 999 साल के लिए लीज पर दे दिया था ताकि बांग्लादेश के दहाग्राम-आंगरपोटा एन्क्लेव के निवासी मुख्य भूमि तक पहुंच सकें। 2015 के भारत-बांग्लादेश एन्क्लेव समझौते के बाद 100+ एन्क्लेव खत्म हो गए, लेकिन दहाग्राम अभी भी खास स्थिति में है।

इस जगह पर भारतीयों को एंट्री के लिए स्पेशल परमिट (ILP जैसा) या स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी दिक्कत के कॉरिडोर से आ-जा सकते हैं। इस इलाके में बांग्लादेशी झंडे, बांग्लादेशी मुद्रा (टका), स्कूल, अस्पताल और कानून व्यवस्था बांग्लादेशी तरीके से चलती है। यहां भारतीय सुरक्षा बल चेकिंग करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन बांग्लादेश के अधीन है। इस एन्क्लेव में करीब 20 हजार बांग्लादेशी नागरिक रहते हैं। यहां की जिंदगी, भाषा, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। लोग बांग्लादेशी मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और बांग्लादेश सरकार की सुविधाओं का लाभ लेते हैं। यह इलाका भारत-बांग्लादेश सीमा की संवेदनशीलता के कारण सुरक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिना अनुमति के जाने पर बीएसएफ रोक सकती है। पर्यटकों और आम भारतीयों को पहले से परमिट लेना या स्थानीय प्रशासन से अनुमति मांगनी पड़ती है। इससे यह जगह भारत में होते हुए भी सामान्य भारतीय इलाकों से अलग हो जाती है।

सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग छात्रों के दर्द को समझें : प्रियंका

» कांग्रेस सांसद ने पेपर लीक मामले में मोदी सरकार को घेरा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। वायनाड की सांसद ने बार-बार परीक्षा के पेपर लीक होने से प्रभावित छात्रों के प्रति एकजुटता जताई और सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों से अपील की कि वे छात्रों और उनके परिवारों की मुश्किलों को समझें। 16 जून को इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी, जिनकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है, हमें छात्रों के साथ खड़ा होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वे किस तरह की मुश्किलों और तकलीफों से गुजरे हैं। हर पेपर लीक हो जाता है। उनके माता-पिता उनके लिए कर्ज़ ले रहे हैं। गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि यह समस्या अलग-थलग नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत समस्या का संकेत है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक गहरी व्यवस्थागत समस्या है, और हमें इसे मिलकर हल करना चाहिए। पेपर लीक कोई एक बार की समस्या नहीं है; यह बनी हुई है। हमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता ने परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधारों की जरूरत पर जोर दिया, ताकि छात्रों का भरोसा बहाल हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगातार हो रही अनियमितताओं की वजह से उनकी मेहनत बेकार न जाए।

अब बदलाव लाने की जरूरत

राहुल बड़े छात्र सम्मेलनों की एक सीरीज करेंगे: वेणुगोपाल

वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी बड़े छात्र सम्मेलनों की एक सीरीज़ करेंगे, जिसकी शुरुआत कोटा (17 जून), इलाहाबाद (10 जुलाई), पटना (11 जुलाई) और दिल्ली (14 जुलाई) से होगी। इन सम्मेलनों में छात्र, परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा, युवा संगठन, शिक्षक और वे सभी लोग शामिल होंगे जो परीक्षा से जुड़े घोटालों से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं।

नेता प्रतिपक्ष ने युवाओं का किया आवाहन

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, युवाओं से जुड़े मुद्दों और कथित परीक्षा घोटालों के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के तहत, पूरे भारत में बड़े छात्र सम्मेलनों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करेंगे। इसकी शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी।

कांग्रेस के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल ने घोषणा की कि आगे के कार्यक्रम 10 जुलाई को इलाहाबाद, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार, युवा संगठन और शिक्षक एक साथ आएंगे।

गोवा में सिर्फ बिल आ रहा बिजली नहीं : केजरीवाल

» आप का बीजेपी सरकार को चेतावनी समस्या नहीं सुलझी तो होगा आंदोलन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पणजी। आप ने बिजली से जुड़ी समस्याओं को लेकर गोवा सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि जरूरी सेवाओं के लिए पैसे चुकाने के बावजूद ग्राहकों को बढ़े हुए बिजली बिल, बकाया राशि के बोझ और बार-बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे राज्य में बिजली की समस्याओं को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार के सामने तीन मुख्य मांगें रखीं। हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए, 15 जून तक का बिजली का बकाया पूरी तरह माफ किया जाए और 24 घंटे बिना रुकावट बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के उपाय किए जाएं।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि कई ग्राहकों को गलत बिल और पेनल्टी चार्ज मिले हैं, जबकि बहुत से लोग जमा हुए बकाया बिलों की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनवरी 24 से मई 25 के बीच गोवा में लगभग 19,000 बार बिजली कटौती हुई, जो बिजली सेक्टर के मैनेजमेंट में कमियों को दिखाता है। यह कहते हुए कि भरोसेमंद बिजली सप्लाई बेहतर प्रशासन का मामला है, केजरीवाल ने कहा कि सरकार को ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 31 जुलाई तक मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आप इस मुद्दे पर राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।

नगर निगम कर्मचारी संघ ने 30 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। नगर निगम कर्मचारी संघ,लखनऊ के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम प्रशासन के समक्ष कर्मचारियों की लम्बित 30 सूत्रीय मांग पत्र पर नगर आयुक्त महोदय के प्रतिनिधि के रूप में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सकारात्मक वातावरण में सम्पन्न हुयी।

वार्ता में मुख्य रूप से रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का द्वितीय श्रेणी लिपिक, क्लीनर से ड्राईवर, माली से प्रधान माली, सहायक अध्यापिका से मुख्य अध्यापिका आदि पदों पर शीघ्र पदोन्नति, निलम्बित कर्मचारियों की शीघ्र बहाली, वर्ष 13 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को सामूहिक बीमा का लाभ दिया जाना, 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन भविष्य निधि के रूप में काटी गयी धनराशि भुगतान हेतु शासन को प्रेषित पत्र की पैरवी हेतु लेखा विभाग के किसी अधिकारी को नामित करना, बीमार एवम् महिला कर्मचारी को उनके घर के निकट स्थानांतरण,कर्मचारियों की व्यक्तिगत पत्रावलियों का सेवाकाल में ही परीक्षण कराया जाना,मृतक आश्रित के शेष लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, छुट्टी के दिन कार्य करने पर प्रतिकर अवकाश जैसे मुद्दों पर सहमति बनी व अन्य मांगों पर विस्तृत चर्चा हुयी। बैठक में अध्यक्ष आनन्द वर्मा और महामंत्री शमील एख़लाक़ द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति पर शीघ्र कार्यवाही का अनुरोध किया।

तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर 1.28 लाख का कर्ज

» टीवीके ने जारी किया सरकार का श्वेत पत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। विजय के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति पर जारी एक श्वेत पत्र के अनुसार, तमिलनाडु की कुल वित्तीय देनदारियां बढ़कर अनुमानित 13.18 लाख करोड़ रुपये हो गई हैं, और राज्य का बकाया प्रत्यक्ष कर्ज 10 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन द्वारा पेश की गई वित्तीय स्थिति रिपोर्ट में बताया गया है कि एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार के तहत पिछले पांच वर्षों में राज्य पर कर्ज का बोझ लगभग दोगुना हो गया है और तमिलनाडु में पैदा होने वाले हर बच्चे पर असल में 1.28 लाख रुपये का कर्ज है।

तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र जिसमें पिछली एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार से मिली वित्तीय स्थिति की समीक्षा की गई है। विजय द्वारा पिछले महीने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद की गई पहली बड़ी घोषणाओं में से एक था। डॉक्यूमेंट के अनुसार, राज्य का सीधा कर्ज़ पांच साल पहले के लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपये से तेज़ी से बढ़कर अभी लगभग 10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। जब ऑफ़-बजट उधार, गारंटी और दूसरी देनदारियों को भी इसमें शामिल किया जाता है, तो राज्य पर कुल वित्तीय बोझ का अनुमान 13.18 लाख करोड़ रुपये लगाया जाता है।

पिछले 5 सालों में जमा हुआ कर्ज उससे पहले के छह दशकों में जमा हुए कुल कर्ज से भी ज्यादा

मंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में जमा हुआ कर्ज़, उससे पहले के छह दशकों में जमा हुए कुल कर्ज़ से भी ज्यादा है। उन्होंने आगे कहा कि उधार का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स बनाने के बजाय रेज़मर्रा के खर्चों को पूरा करने में इस्तेमाल किया गया है। तमिलनाडु का बकाया कर्ज़-नेशनल अनुपात 28.2 प्रतिशत है, जबकि पिछले पांच सालों में रेवेन्यू घाटा 46,538 करोड़ रुपये से बढ़कर 78,324 करोड़ रुपये हो गया है, जो रेवेन्यू प्राप्ति और खर्च के बीच बढ़ते अंतर को दिखाता है।

एआईडीएमके को लगा करारा झटका

» विरलिमलाई विधायक विजय भास्कर ने दिया इस्तीफा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

चेन्नई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विरलिमलाई विधायक सी. विजयभास्कर ने अपने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जिससे विरलिमलाई सीट तत्काल प्रभाव से खाली हो गई है। यह घटना तमिलनाडु में एआईडीएमके के लिए बढ़ते राजनीतिक संकट का संकेत है।

विजयभास्कर ने विधानसभा नियम 21 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना इस्तीफा पत्र खुद सौंपा। स्पीकर ने कहा कि इस्तीफे की जांच की गई और पाया गया कि यह विधानसभा नियम 22 के अनुरूप है। इसके बाद, इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। इस्तीफा स्वीकार होने के साथ ही, विरलिमलाई विधानसभा क्षेत्र की सीट तत्काल प्रभाव से खाली हो गई है।

सेमीफाइनल की राह आसान करने उतरेगी टीम इंडिया

» पाकिस्तान को रौंदने के बाद नीदरलैंड से मुकाबला आज

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लीड्स। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में भारत ने जीत तो दर्ज की, लेकिन बल्लेबाजी पूरी तरह प्रभावी नहीं दिखी। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और निचले क्रम में ऋचा घोष ने महत्वपूर्ण पारियां खेलकर टीम को संभाला, लेकिन अन्य बल्लेबाज अपेक्षित योगदान नहीं दे सके। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा, कप्तान हरमनप्रीत कौर और मध्यक्रम की बल्लेबाज भारती फुलमाली बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहीं। ऐसे में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला भारतीय बल्लेबाजों के लिए लय हासिल करने का अच्छा अवसर होगा।

पहले मैच में भारतीय स्पिनरों ने शानदार प्रदर्शन किया था। दीप्ति शर्मा और श्री चरणी की जोड़ी ने मिलकर आठ विकेट झटके थे। हालांकि तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी और क्रांति गौड़ ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ सकीं। दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में शुरुआती विकेट निकालकर अपनी छाप छोड़ना चाहेंगी।

पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की फील्डिंग शुरुआत में कुछ कमजोर रही थी। हालांकि बाद में खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे कैच लपके, लेकिन बड़े मुकाबलों से पहले टीम को इस विभाग में और सुधार करना होगा। भारत को ग्रूप चरण में आगे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों का सामना करना है। ऐसे में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला तैयारियों को मजबूत करने का अवसर भी होगा।

बांग्लादेश से हारने के बाद दबाव में हैं नीदरलैंड

नीदरलैंड्स की टीम अपना पहला मैच बांग्लादेश से हारकर आ रही है। कप्तान बाबेट डी लीडे ने भी माना कि उनकी टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। उन्होंने कहा, खेल के तीनों विभागों में हम वह प्रदर्शन नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद थी। बल्लेबाजी में हम कुछ रन पीछे रह गए और फील्डिंग में भी हमने कुछ कैच छोड़े। हमें काफी कुछ सीखना और सुधारना होगा। भारत इस मुकाबले में जीत की प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन टीम की नजर सिर्फ दो अंक हासिल करने पर नहीं बल्कि बल्लेबाजी और फील्डिंग में कमियों को दूर करने पर भी होगी।

अजब-गजब : यूपी के सुशासन की खुली पोल

» फरियाद लेकर पहुंचा कागजों में मुर्दा किसान, महमूदाबाद तहसील क्षेत्र का है मामला

» किसान ने जिलाधिकारी को प्रेषित किया प्रार्थना पत्र

» 28 बीघा पैतृक भूमि की वरासत चार भतीजों के नाम दर्ज होने का दावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क/ वली चौधरी

सीतापुर। यूपी की योगी सरकार सुशासन की बाते करती हैं पर सीतापुर जिले के गांजरी इलाके में अलग कहानी है। कभी काग़ज़ की कश्ती है कभी बारिश का पानी है। इस बार न बारिश है न ही कागज की कश्ती। इस बार कागजों के खेल से कई लोग परेशान और हलकान हो गए हैं। गांजर के किसानों की तस्वीर भी बाढ़ के पानी की थपेडों की तरह है। एक किसान को काग़ज़ों पर मुर्दा दिखा दिया गया। जबकि वो ज़िंदा तहसील प्रशासन के चक्कर लगाने वाले किसान ने परेशान होकर जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है।

मामला महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के बाढ़ और कटान प्रभावित क्षेत्र के दुर्गापुर गांव से जुड़ा हुआ है। महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के दुर्गापुर मजरा हरिहरपुर निवासी परसराम पुत्र पराग ने आरोप लगाया है कि उनके पिता पराग की मृत्यु के बाद करीब 28 बीघा पैतृक भूमि का बंटवारा हुआ था। उनके भाई बनवारी के चार पुत्र हैं। करीब दस वर्ष पूर्व बनवारी की भी मृत्यु हो चुकी है। परसराम का कहना है कि वह गाटा संख्या 205(ख), 178, 162, 207, 193 और 148 स्थित भूमि में सहखातेदार एवं भूमिधर हैं।

आरोप है कि भाई बनवारी की मृत्यु के बाद उनके चारों पुत्रों ने वरासत दर्ज कराने के लिए आवेदन किया। आरोप है कि इसी दौरान राजस्व निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्हें अभिलेखों में मृत दर्शा दिया। इसके बाद उनके हिस्से की भूमि भी चारों भतीजों के नाम वरासत में दर्ज कर दी गई। इनका दावा है कि तहसील प्रशासन में एसडीएम, तहसीलदार से कई बार शिकायत कि मगर कहीं से कोई राहत नहीं मिली। थक हार कर कई माह बाद परसराम ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से दावा किया गया है कि किसान ज़िंदा है, उसके हिस्से में लगभग 14 बीघा भूमि है, जिसपर उसका अधिकार है। उसके बवाजूद भी अभिलेखों में हेरफेर करते हुए उसे मृत दिखाया गया है।

> “आरोप पूरी तरह निराधार हैं। वरासत की प्रक्रिया लेखपाल के पोर्टल से संचालित होती है, कानूनगो सीधे वरासत नहीं करता। संभवत: गाटा संख्या चिह्नित करने में तकनीकी त्रुटि हुई है। शिकायतकर्ता से दो-तीन दिन का समय मांगा गया है। दुरुस्तीकरण की कार्रवाई जारी है और जल्द रिकॉर्ड सही कर दिया जाएगा।- वीरेंद्र सिंह, राजस्व निरीक्षक

> “शिकायत की जांच कराई जा रही है। यदि राजस्व अभिलेखों में किसी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उसे नियमानुसार ठीक कराया जाएगा। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।-अंजली सिंह, एसडीएम महमूदाबाद

अदालत ही तय करेगी कि असली टीएमसी कौन : सुदीप बंदोपाध्याय

» बोले बागी सांसद- अगर पार्टी के दो-तिहाई सांसद पार्टी छोड़ देते हैं, तो यह संवैधानिक रूप से जायज है

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। बागी तृणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि अदालत ही तय करेगी कि असली टीएमसी कौन है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि अगर पार्टी के दो-तिहाई सांसद पार्टी छोड़ देते हैं, तो यह संवैधानिक रूप से जायज़ है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हालात में इसे धोखा नहीं माना जाएगा। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में विलय करने और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एनडीए) का समर्थन करने का इरादा ज़ाहिर किया है।

उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाक़ात की और तृणमूल कांग्रेस से अलग अपनी पहचान को मान्यता देने का अनुरोध किया। बंद्योपाध्याय ने पत्रकारों से कहा कि कुल 20 लोकसभा सांसद हैं... अगर 2/3 सांसद अलग हो रहे हैं, तो यह धोखा नहीं है। देश का संविधान इसकी इजाज़त देता है। लोकसभा भी इसकी इजाज़त देती है। अगर संख्या 2/3 से कम होती, तो यह धोखा होता... असली टीएमसी कौन है, इसका फ़ैसला कोर्ट करेगा। एक और बागी सांसद, रचना बनर्जी ने कहा कि वे हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सम्मान करेंगी, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया और टीएमसी के 15 साल के शासनकाल में आने वाली मुश्किलों का ज़िक्र किया। विलय के दस्तावेज़ पर दस्तख़त करने के लिए विदेश से लौटीं बनर्जी ने माना कि वोट दीदी (ममता बनर्जी) की वजह से मिले थे, लेकिन साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया कि वोटर विकास की उम्मीद करते हैं। सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी के खिलाफ़ कभी बगावत नहीं कर सकते और उनके मन में हमेशा उनके लिए सम्मान रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी सरकार के कामकाज की रफ़्तार की तारीफ़ करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने से काम करना आसान होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट पर टेलीग्राम

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आगामी 21 जून को होने वाले नीट-यूजी री-टेस्ट (दोबारा परीक्षा) से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने पेपर लीक और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म (टेलीग्राम) को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस कड़े कदम के खिलाफ टेलीग्राम कंपनी ने सीधे दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।

यह मामला जस्टिस तेजस करिया की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, जिस पर अदालत ने आज ही विस्तार से सुनवाई करने की सहमति दे दी है। परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक विवाद की जांच वर्तमान में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) कर रही है। सीबीआई की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र को पीडीएफ फॉर्मेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से सर्कुलेट किया गया था, जिससे परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता पूरी तरह प्रभावित हुई। आगामी री-टेस्ट में सुरक्षा की किसी भी तरह की दोबारा चूक या अनधिकृत परीक्षा सामग्री को फैलने से रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने सुरक्षात्मक उपाय के तौर पर टेलीग्राम पर यह अस्थायी प्रतिबंध लगाया है।

कलकत्ता हाईकोर्ट का बंगाल के स्पीकर को फटकार

» बोली अदालत टीएमसी के नाम को नजरअंदाज कैसे किया, नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर पूछे तीखे सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति का विवाद कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस से कई सवाल पूछे हैं कि क्या अध्यक्ष बहुमत वाले दल के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर सकते हैं और क्या वह दोनों पक्षों को सुने बगैर नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं।

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की तरफ से दो नाम विधानसभा अध्यक्ष को मिले, एक नाम पार्टी के बागी विधायकों ने भेजा, जबकि दूसरा नाम पार्टी नेतृत्व की तरफ से भेजा गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष के लिए एक ही राजनीतिक दल से दो अलग-अलग प्रस्ताव मिलें तो विधानसभा अध्यक्ष को कौन सी प्रक्रिया अपनानी चाहिए. पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस तरह का विवाद पहली बार अदालत के समक्ष आया है। विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बसु ने बागी गुट की ओर से भेजे गए ऋतब्रत बनर्जी के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। एडवोकेट बिल्वदल भट्टाचार्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति विवाद का विषय बनी है, कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी।

वडोदरा में बड़ा सड़क हादसा, जरोद हाईवे पर ट्रक में जा घुसी स्लीपर बस, 6 लोगों की मौत और 31 घायल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

वडोदरा। वडोदरा-जरोद रोड पर आज सुबह-सुबह एक बेहद दर्दनाक और भीषण सड़क हादसा हो गया। कोटंबी गांव के पास हाईवे पर एक लक्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बस में सवार करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह हादसा आज तड़के (सुबह-सुबह) हुआ। हाईवे से गुजर रही एक लक्जरी बस अचानक आगे चल रहे एक ट्रक के पिछले हिस्से में बेहद तेजी से जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस जोरदार टक्कर की वजह से बस के अंदर बैठे 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हादसे के वक्त बस में चीख-पुकार मच गई। टक्कर के कारण 31 यात्रियों को गंभीर चोटें आई हैं।

एक्सीडेंट की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत वडोदरा के प्रसिद्ध सयाजी अस्पताल ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। हादसे की गंभीरता को देखते हुए बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम को बुलाया गया।

रायपुर एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, दिल्ली से आ रही एअर इंडिया फ्लाइट से पक्षी टकराया

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर बुधवार सुबह एअर इंडिया की दिल्ली-रायपुर उड़ान बर्ड हिट की चपेट में आ गई। विमान की लैंडिंग के दौरान पक्षी टकराने की घटना हुई, जिसके बाद एहतियात के तौर पर विमान का तकनीकी निरीक्षण किया गया। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के अनुसार एअर इंडिया की फ्लाइट सुबह 8.15 बजे रायपुर पहुंचने वाली थी। विमान ने सुबह करीब 8:08 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, इसी दौरान विमान से पक्षी के टकराने की घटना हुई। बर्ड हिट की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट और एयरलाइन प्रबंधन ने सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत विमान का विस्तृत तकनीकी परीक्षण शुरू कराया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यही विमान सुबह 8.55 बजे रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होने वाला था, लेकिन तकनीकी जांच और सुरक्षा मंजूरी मिलने तक उड़ान को रोके रखा गया। करीब ढाई घंटे तक चले निरीक्षण के बाद विमान को उड़ान के लिए फिट घोषित किया गया।

नीतीश की वजह से सब परेशानी हो रही है: लालू

बंगला और सुरक्षा कटौती विवाद के बीच राजद प्रमुख बरसे

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने अपनी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती तथा सरकारी आवास विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर किया गया है।

लालू प्रसाद ने कहा कि उनकी और राबड़ी देवी की सुरक्षा कम कर दी गई है। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसके पीछे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका है। दरअसल, एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से सरकार को पत्र भेजकर 10, सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। उनके सचिव द्वारा भेजे गए पत्र में आग्रह किया गया है कि जब तक राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद की सदस्य हैं, तब तक उन्हें उसी आवास में रहने की अनुमति दी जाए। राबड़ी देवी का विधान परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल 6 मई 2030 तक है। वहीं, भवन निर्माण विभाग की ओर से बंगला खाली करने के लिए निर्धारित समय-सीमा 15 जून को समाप्त हो चुकी है। ऐसे में नियमों के अनुसार प्रशासन आगे की कार्रवाई कर सकता है।

महाराष्ट्र कार्यालय :- 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क, 2-डी सिटी मॉल, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400053। विधि सलाहकार : मोहम्मद हैदर
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी।
RNI-UPHIN/2015/62233, दूरभाष: 0522- 4078371 | Email: daily4pm@gmail.com | website: www.4pm.co.in |
समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।
स्वामी 4 पीएम न्यूज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए
मुद्रक एवं प्रकाशक संजय शर्मा
द्वारा आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से मुद्रित
पता 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (यूपी) से प्रकाशित। संपादक- संजय शर्मा